Every time, whenever there is a flood or a brought, they suffer all the more So, there should be some sort of crop insurance to cover pady I also want to know whether the scheme will be extended to Kerala

SHRI BHANU PRATAP SINGH The Kerala State Government is associated with this scheme Actually, their representatives were with us and they have disucessed their special problems also with us

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा किन-किन राज्यो मे आप ने इस का सर्वेक्षण किया है--क्या वहा की राज्य सरकारो से इस सम्बन्ध मे आवश्यक वार्ता आप ने की है यदि हा तो उसका क्या परिणाम निकला है ? यदि निकला है तो उस को देखते हुए उस के अनुसार कब तक आप इस मे ठोस कदम उठा सकेगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह राज्य सरकारो के प्रतिनिधि आये थे और हमारे साथ वार्ता हुई थी। परन्तु उन्हो ने कहा कि अतिम निर्णय वे वापिस जा कर कभी लेगे ? अभी उन का अन्तिम निर्णय प्राप्त नही हुआ है । इस सम्बन्ध मे असम, गुजरात, आध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक राजस्थान और केरल राज्यो मे बातचीत चल रही है और उन राज्यो के विषय मे प्रीमियम इडेमनिटी टेबल्ज वगैरह भी तैयार किए जा रहे है । यदि इन राज्य सरकारो न स्वीकार कर लिया तो अगली खरीफ मे सम्भवत यह स्कीम लागू की जा सकेगी ।

उपजाऊ भूमि में पानी का जमा होना

*455. **श्री विनायक प्रसाद यादव :**

क्या कृषि और सिंचाई मत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि

(क) क्या विभिन्न सिंचाई योजनाओ को अवैज्ञानिक तथा अव्यवस्थित ढग से क्रियान्वित किये जाने के कारण देश मे विशेषकर बिहार मे कई लाख हैक्टेयर उपजाऊ भूमि मे पानी जमा हो गया है जिस से बहुत ज्यादा नुक्सान हो रहा है और छोटे किसान और गरीब हो रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पम्पो द्वारा पानी निकालने की कोई योजना बनाई है, और

(ग) यदि हा, तो इस प्रयोजन के लिए बिहार को कितनी राशि दी गई तथा पानी का इस तरह जमाव कब समाप्त होगा ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House

Statement

(a) waterlogging is caused by rise of sub-soil water level within and above the root zone which affects adversely the productivity of the soil Introduction of irrigation can cause waterlogging under certain conditions Waterlogging conditions had earlier developed in certain areas within the commands such as Sirhind Canal and Upper Bari Doab Canal System in Punjab, Western Yamuna Canal in Haryana and Chambal in Madhya Pradesh and Rajasthan but the problem in these projects is under control as a result of introduction of drainage and conjunctive use of surface and ground water Waterlogging conditions however do prevail in certain pockets of irrigation commands

So far as Kosi and Gandak projects concerned there is drainage congestion due to natural depressions and unfavourable outfal conditions during monsoon

(b) and (c) Irrigation projects now provide for appropriate drainage measures and the problem areas are now being tackled by the State Governments by means of measures such

and sub-surface drains, conjunctive use of surface and ground water etc. to control the water table.

The Government of Bihar have made a provision of Rs. 20 crores and Rs 27 crores for drainage in the revised project estimates for Kosi and Gandak projects respectively for improving the drainage conditions and the works have been taken in hand These projects are expected to be completed in the next 5-6 years.

श्री विनायक प्रसाद यादव : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर मे यह लिखा है :— जहा तक कासी और गडक परियोजनाओ का सम्बन्ध है, प्राकृतिक गढो और जल निकासी की व्यवस्था के प्रतिकूल होने के कारण मौनसून के मौसम मे जल निकास मे रूकावट पैदा हो जाती है ।

जहा तक इस जवाब का सम्बन्ध है हम समझते है कि यह बिल्कुल गलत जवाब है इस पानी मे कि वहा जो नहर बनी है कोसी की और गडक की उस के पहले जो उपजाऊ जमीन थी जिस मे कभी पानी नही लगता था नहर बनने के बाद वहा पर फाजिल पानी का निकास कर दिया जाता है और उस की वजह से जो उपजाऊ जमीन है उसमे वहपानी आ कर के जमा हो जाता है और उस के वहा से निकलने की कोई व्यवस्था नही है । क्या मंत्री महोदय बता सकते है कि गडक और कासी कमाड एरिया मे कितनी जमीन अभी तक वाटर लाग्ड हुई है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : कोसी कमान्ड एरिया है मे 1. 12 लाख हैक्टेयर जमीन वाटर लाग्ड हुई है और गडक कमाड एरिया मे 2. 95 लाख हैक्टेयर जमीन वाटर लाग्ड है ।

श्री विनायक प्रसाद यादव : जैसा मंत्री महोदय ने कहा मैं अध्यक्ष जी, आप के जरिये इन से कहना चाहता हू कि कोसी में जो अभी सिंचाई हो रही है उस मे मुश्किल से 2 लाख हैक्टेयर जमीन मे सिंचाई हुई है, जब कि उसी कोसी नहर के चलते जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया 1 लाख हैक्टेयर से ज्यादा जमीन में पानी जमा हो गया है और उस के निकालने के लिये मंत्री जी ने कहा है कि बिहार सरकार ने कोसी योजना मे 20 करोड रु० दिया है वाटर निकालने के लिये और गडक योजना मे 27 करोड रु० दिया है । तो मैं पूछना चाहता हू कि यह रुपया कब दिया गया, कितने दिन से स्कीम चल रही है, कितनी जमीन मे से पानी को निकाला गया है कोसी और गडक योजना मे और कितना रु० हर साल ड्रेनेज विभाग ने वापस सरकार का लौटा दिया काम न कर के और वह रुपया लैप्स हो गया है ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जवाब मे बताया गया है कि बिहार सरकार ने 20 करोड रु० कोसी के लिये और 27 करोड रुपया रिवाइज्ड प्राजैक्ट ऐस्टीमेट गडक के लिये बनाया है । पहले जो ओरीजनल स्कीम थी उस मे ड्रेनेज के लिये बहुत थोडा प्राविजन किया गया था । कोसी प्रोजैक्टट मे महज 1 करोड 32 लाख का एमूवल था और गडक मे 42 लाख का प्रावीजन था जिस को बढा कर 27 करोड कर दिया गया है और इस मे काम शुरू किया जा रहा है और आशा है कि 5, 6 साल मे यह सारा काम पूरा हो जाएगा ।

श्री विनायक प्रसाद यादव : ड्रेनेज डिपार्टमेंट 5, 7 वर्ष से कोसी और गडक मे काम कर रहा है, मैं पूछना चाहता हू कि कितना काम हुआ है ? लाखो ऐकड जमीन कोसी और गडक योजना के चलते वाटर लाग्ड हो गई है इस का जवाब दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नही आप सवाल पूछ चुके है ।

श्री डी० एन० तिवारी : यह सुन कर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि गंडक कमान्ड एरिया में करीब 3 लाख एकड़ जमीन वाटर लाग्ड है । मैं जानना चाहता हूं कि कितनी जमीन की सिंचाई उससे होती है और 3 लाख एकड़ के करीब जो जमीन वाटर लाग्ड है उसमें कुछ होता नहीं है तो उससे कितना नुकसान हर साल होता होगा ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : नुकसान का तो अंदाजा नहीं लगाया गया है कि कितना नुकसान होता है ।

श्री डी० एन० तिवारी : कितने एरिया में सिंचाई होती है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : टोटल सिंचाई कितनी होती है इससे संबंधित यह सवाल नहीं था इसलिए उस के फ़ैक्ट्स नहीं बता सकूंगा । अलग से सवाल करें तो जवाब दूंगा ।

श्री बी० पी० मण्डल : कोसी में जितनी जमीन की सिंचाई होती है उससे ज्यादा जमीन, अच्छी जमीन, डिफ़ेक्टिव ऐलाइनमेंट के कारण वाटर लाग्ड हो जाती है और वही हालत गंडक की भी है । क्योंकि भारत सरकार देश की उपज को बढ़ाना चाहती है, तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस किस्म का जो वाटर लागिंग है, और बिहार सरकार का मैं यह भी कह दूं कि रुपया लैप्स कर जाता है, काम नहीं होता है, तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट इस में कहां तक इंटरेस्ट लेना चाहती है देश की उपज बढ़ाने के लिये ? वाटर लागिंग की प्रोबलम को दूर करने के लिये आपका पर्सनली कितना इंटरेस्ट है ?

MR. SPEAKER: It is a suggestion.

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इरीगेशन और फ्लड कंट्रोल स्टेट सबजेक्ट है इसलिए मैनली स्टेट्स ही स्कीम बनाती हैं और ऐग्जीक्यूट करती हैं और फ़ाइनेंस करती हैं । इसीलिये स्टेट गवर्नमेंट ने यह 42 लाख से बढ़ाकर 27 करोड़ रु० किया है । उन्होंने समझा है कि इस प्रौब्लम को जल्दी से जल्दी हल करना चाहिये और वह इस काम पर लगी हुई है । जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं बहुत देर से यह मसला है, इसमें बहुत काम अभी तक नहीं हो सकता है । लेकिन अब आगे काम अच्छी तरह से होगा । हम भी इसमें दिलचस्पी लेंगे और स्टेट गवर्नमेंट भी दिलचस्पी ले रही है ।

Payment to re-employed teachers of Aided Schools in Delhi

*460. SHRI BALAK RAM: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the services of some teachers working in Government aided schools of Delhi had been terminated after declaring them as unqualified;

(b) whether it is also a fact that some of the teachers whose services had been terminated were found qualified only after intervention of his Ministry and thus given re-employment;

(c) whether it is also a fact that such teachers have not been paid their emoluments for the above said intervening period which varies from months to years; and

(d) what remedial steps are being taken by the Central Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRIMATI RENUKA DEVI BARAKATAKI). (a) to (d). A statement is laid on the Table of the Sabha.